



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 कार्तिक, 1941 (श०)

संख्या- 915 राँची, शुक्रवार, 8 नवम्बर, 2019 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

राज्यादेश

18 अक्टूबर, 2019

संचिका संख्या-5/स०भू० बोकारो (IOCL)-141/19-3930/रा०,--
सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची।

विषय:-

मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-15.10.2019 में मद संख्या-09 के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में बोकारो जिलान्तर्गत अंचल-चास के मौजा-बुढ़ीविनोर, थाना सं०-81, खाता सं०-125, प्लॉट संख्या-02 में अंतर्निहित कुल रकबा-0.72 एकड़ गैरमजरूआ खास किस्म-पुरातन पतीत भूमि (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक-I) राजस्व विभागीय संकल्प सं०-48/रा०, दिनांक-03.01.17 के आलोक में प्रस्तावित भूमि के वर्तमान बाजार दर के आधार पर की गयी सलामी की राशि 10,80,000/- (दस लाख अस्सी हजार) रुपये मात्र, सलामी का 1 (एक) प्रतिशत वार्षिक लगान की राशि 10,800/- (दस हजार आठ सौ) रुपये, लगान का 75 प्रतिशत सेस की राशि 8,100/- (आठ हजार एक सौ) रुपये मात्र तथा 29 वर्षों के लिए एकमुश्त भुगतये लगान एवं

सेस की राशि **5,48,100/-** (पाँच लाख अड़तालीस हजार एक सौ) रुपये मात्र अर्थात् कुल देय राशि **16,47,000/-** (सोलह लाख सैंतालीस हजार) रुपये मात्र (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक-II) की अदायगी पर **IOCL** के सिटी गैस स्टेशन प्रोजेक्ट के निर्माण हेतु **Indian Oil Corporation Limited (IOCL)** के साथ **30** वर्षों के लिए नवीकरण विकल्प के साथ सशुल्क लीज बंदोबस्ती के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत।

- i. जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा **12** माह में कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने पर यह भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जाएगी।
- ii. उपायुक्त, बोकारो प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण से संबंधित सभी खातों एवं प्लॉटों में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई करेंगे।
- iii. यदि परियोजना के अंतर्गत वृक्षादि है तो वैसी स्थिति में वृक्षों की लागत मूल्य की गणना कर एकरारनामा के समय कंपनी से राशि प्राप्त कर ली जायेगी।
- iv. प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण की तिथि को भूमि के वर्तमान मूल्य के आधार पर सलामी एवं लगान तथा सेस की गणना कर अंतर की राशि प्राप्त कर संबंधित उपायुक्त द्वारा भूमि की लीज बंदोबस्ती की जायेगी। परन्तु प्रस्तावित भूमि के मूल्य से यदि कम होता है तो अनुमोदित राशि की ही वसूली कर भूमि की लीज बंदोबस्ती की जायेगी। किसी भी परिस्थिति में यह राशि अनुमोदित राशि से कम नहीं होगी। अगर परियोजना से संबंधित दर/सलामी, लगान एवं सेस सहित राशि में अंतर परिलक्षित होता है तो अंतर राशि को संबंधित उपायुक्त द्वारा एकरारनामा करने के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी। उपायुक्त, बोकारो यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि यदि भविष्य में किसी प्रकार की देयता होती है तो अंतर राशि अधियाची निकाय द्वारा भुगतये होगा। एकरारनामा में यह शर्त भी सन्निहित रहेगा।
- v. उपायुक्त संतुष्ट हो लेंगे कि प्रस्तावित भूमि विवादरहित तथा वनसीमा/भू-हदबंदी/ भू-दान/कब्रिस्तान/शमशान/धार्मिक स्थल से मुक्त है।
- vi. अन्य सभी शर्तें राजस्व विभागीय संकल्प सं०-48/रा०, दिनांक-03.01.17, विभागीय संकल्प संख्या-4306/रा०, दिनांक-24.10.14 एवं खासमहाल इस्टेट मैनुअल में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुनील कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक-I

IOCL के साथ लीज बंदोबस्ती हेतु प्रस्तावित भूमि की विवरणी :-

क्र०	अभिलेख सं०	ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़)	भूमि का किस्म
01	02/2019-20	बुढ़ीविनोर	81	125	02	0.72	पुरातन पतीत
कुल-						0.72	

अनुलग्नक-IIप्रस्तावित भूमि के मूल्य की गणना :-

क्र०	अभिलेख सं०	रकबा (एकड़)	प्रति एकड़ मूल्य	सलामी की राशि	लगान (सलामी का 1%)	सेस (लगान का 75%)	लगान एवं सेस 29 वर्षों के लिए	कुल राशि (5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	02/2019-20	0.72	1500000	1080000	10800	8100	548100	1647000

अर्थात् कुल देय राशि 16,47,000/- (सोलह लाख सैंतालीस हजार) रुपये मात्र।

सरकार के संयुक्त सचिव
